I, therefore, urge upon the Central Government to rush to provide assistance to Kerala and sanction an assistance of at least Rs. 200 crores to meet the drought situation.

(iii) Bank loans to people of Gujarat whose houses were destroyed in recent cyclone.

SHRI NAVIN RAVANI (Amreli) : With a view to bringing relief to those whose houses were damaged or destroyed during the cyclone which hit certain parts of Gujatat mainly the districts of Amreli, Bhavnagar and Junagadh, the Central & State Governments have promptly made arrangements for relief and have through the R.B.I. instructed nationalised Banks to provide housing loans to the affected persons on easy terms.

It is, however, observed that the progress of the Banks in giving loan is not at all satisfactory. In urban areas most of the applications for loans have been rejected on technical grounds. The situation in rural areas is still worse. Hardly and application for loan has been sanctioned in the rural areas.

The plight of these unfortunate people can well be realised that they with their little ones are still under the scorching sky and when rain sets in, which is not far off, their plight will be agravated.

I need not over-emphasise the matter because the Finance Minister had personally visited the affected areas and seen for himself the sad conditions under which these people are living.

I, therefore, request the hon. Finance Minister kindly to issue necessary instructions for the grant of loans so that the relief work can be undertaken immediately.

(iv) Need to improve the functioning of telephones at Mathura, Uttar Pradesh.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : श्रीमन्, मथुरा नगर में टेलीफोन का डायल सिस्टम हो गया है। मथुरा में टेलीफोन की व्यवस्था असाधारण रूप से खराब है। अधिकतर टेलीफोन इसलिये खराब रहते हैं। मैं दो टेलीफोन इसलिए रखता हूं कि एक खराब होगा तो दूसरे से काम चल जायेगा। लगभग दोनों ही खराब रहते हैं। कभी दिल्ली से मथुरा बात करना चाहता हूं तो बहुदा नहीं हो पाती। जनता को बहुत परेशानी है। वहां के एस० डी० ओ० टी० तो मेरे किसी पत्र का उत्तर तक नहीं देते। मैंने 24.2.83 को महाप्रबन्धक दिल्ली को पत्र लिखा। अपने 3 मार्च, 1983 के पत्र में लिखा कि उन्होंने मेरा पत्र लखनऊ के टेलीफोन महाप्रबन्धक को भेज दिया है।

मैं नहीं समझता कि मुझे क्या करना चाहिये ताकि मथुरा नगर और मेरी समस्या हल हो और यह भी पता लगे कि एस० डी० ओ० टी० मथुरा संसद सदस्य की शिकायत पर भी क्यों ध्यान नहीं देते।

कृष्ण जन्म भूमि में जनता भगवान से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करने आती है। मैं उस पवित्र नगरी की ओर से अपनी प्रार्थना सरकार से करता हूं कि वहां की टेलीफोन व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें।

14.00 Hrs.

(v) Working the Telegraph and Telecommunication services in the country.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा हुआ, चौधरी दिगम्बर सिंह जी के बाद मुझे भी उसी समस्या पर बोलना पड़ रहा है।

मैं दूर-संचार की अकार्यकुशलता को सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। यह मेरा और अन्य अनेक व्यक्तियों का अनुभव रहा है कि जो ट्रंक-काल बुक की जाती है, उनके मिलने में काफी समय लगता है और वह ट्रंक-काल भी ट्रंककाल अधिकारियों को कई बार याद दिलाए जाने के बाद मिलती है। बहुधा ये ट्रंक-काल बिल्कुल नहीं मिलते। टेलीफोन एक्सचेंज से जब सम्पर्क किया जाता

है तो वे, जिस व्यक्ति ने काल बुक की है, उसे यह सूचना देते हैं कि लाइन खराब है। इससे काफी असुविधा तथा कठिनाई होती है, विशेष कर वह मामला जिसके लिये ट्रंक-काल का उपयोग किया जाता है, अविलम्बनीय लोक-महत्व का हो।

एक अन्य मामला जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है कि जब एक बार स्मरण कराये जाने पर भी वह नहीं मिल पाती तो काल को रद्द करा पाना और भी अधिक कठिन होता है।

एस० टी० डी० कालों के बारे में मैंने यह देखा है कि प्राय: टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिल पाता है।

इस बारे में मैं एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। मेरी आधे-घंटे-की-चर्चा के बारे में 7 अप्रैल को मेरे स्थायी पते पर लोक-सभा सचिवालय ने एक अविलम्ब ट्रंक-काल बुक किया था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ट्रंक काल के लिए चार बार स्मरण कराने पर भी वह नहीं मिल सका तथा मुझे ठीक समय पर जानकारी नहीं मिल पायी। लोक-सभा सचिवालय द्वारा 6 अप्रैल को भेजा गया टेलीग्राम भी मुझे 9 अप्रैल, 1983 की शाम को मिला।

जब सर्वोच्च सदन के सचिवालय द्वारा अथक प्रयास के बाद भी अपने सदस्यों से सम्पर्क इन माध्यमों द्वारा नहीं किया जा सकता तो साधारण जनता की दुरावस्था का आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह तार व दूर-संचार सेवाओं सम्बन्धी शिकायतों की विशेष रूप से जाँच करें और उन्हे अविलम्ब दूर करें।

(vi) Need for early re-opening of Bhaskar Textile Mills, Jharsuguda.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): I make the following statement under Rule 377.

The closure of Bhaskar Textile Mills, Jharsuguda from 10th January, 1983 has resulted in starvation of 3000 workers and their family members. This closure is causing deep resentment of the entire population of the area since its economy is greatly affected due to this closure. The company started from 1963-64 with investment of Rs. 35 lakhs. It earned a fabulous profit of over Rs. 3 crores till 1980-81. The owner of the company however indulged in several irregularities. When the workers were agitating for payment of bonus and the company on 1.10.82 fixed 16th October, 1982 for discussion with Jharsuguda Industrial Mazdoor Union it surreptitiously issued lockout notice on 2nd Oct, 82 though it was signed on 30th Sept. 82. Since 2nd October 1982 lockout became operative rendering thousands of workers jobless. At present it is still continuing despite repeated efforts by the Union to reopen the mill, and they demanded 1) immediate take over by NTC, opening it immediately by taking back all the workers who were on the rolls on 1.10.82, (2) payment of wages for the lock out period. Therefore, I urge the Government to take steps to meet up their just demands.

(vii) Need for providing speed boats to Custumes Collectorate of Madurai to curb smuggling.

SHRI M.S.K. SATHIYENDRAN (Ramanathapuram): Sir, the Collectorate of Central Excise and Customs at Madurai has under its jurisdiction the east coast from Rameshwaram upto near about Madras. With the duty free shops having been opened at Colombo in Sri Lanka, the smuggling along this long coast-line has gone beyond normal patrolling. Whenever the Customs officials get any information they have to approach through correspondence. the Department of Fisheries or the Naval Coast Guard for loaning speed boats to chase the smugglers. By the time the formalities are fulfilled and the boats are made available, the smugglers run away. It has become essential that the Customs Collectorate at Madurai should be provided immediately with two speed boats so that the smuggling activities are curbed effectively on the east coast. Besides, these speed boats may also stop the poaching being done by some adjoining for. countries on our territorial waters, particularly along the